

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को समूचे प्रदेश में लागू करने के लिये बैठक आयोजति

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2022 को 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को समूचे राजस्थान में लागू करने के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता तथा आयोजना मंत्री ममता भूपेश की अध्यक्षता में चिल्ड्रेंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) तथा सहयोगी संस्था आईपीई ग्लोबल के साथ बैठक आयोजति की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं के लिये लागू करने की घोषणा के अनुसार आने वाले समय में इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर 6 हजार रुपए की राशि महिलाओं को जच्चा-बच्चा पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिये दी जाती है। यह राशि सीधे ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह राजस्थान सरकार का समूचे देश में अनूठा नवाचार है।
- राज्य के टीएसपी क्षेत्र के पाँच जिलों में जहाँ अतः कुपोषित बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पछिले साल से 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' को चलाया गया है। योजना को संचालित करने में सीआईएफएफ और आईपीई ग्लोबल संस्था सहयोग प्रदान कर रही है।
- गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभागों में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग के उद्देश्य से चिल्ड्रेंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) राजस्थान सरकार के साथ अनुबंध के आधार पर कार्य कर रही है।
- इसके अंतर्गत सीआईएफएफ के माध्यम से सहयोगी संस्था आईपीई ग्लोबल राजपुष्ट कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग को 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' एवं 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण' के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।